Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

ASCI
Agriculture Skill Council of India

CEASI
CENTRES OF EXCELLENCE FOR AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

COE हार्वेस्ट

8 सितंबर २०२५

CEDSI
CENTRE OF EXCELLENCE FOR DAIRY SKILLS IN INDIA

CEFMI
Centre of Excellence for Farm Mechanization Skills in India

CEHSI
Centre of Excellence for Horticulture Skills in India

www.ceasi.in

प्रिय पाठकों,

हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के माध्यम से आप तक पहुँच पाना हमारे लिए एक विशेषाधिकार है। यह समाचार पत्र CEASI की गतिविधियों की धड़कन को दर्शाता है, जो ASCI के संरक्षण में कार्यरत है, और हमारे सामूहिक सफ़र को कौशल विकास एवं सतत कृषि की दिशा में प्रतिबिंबित करता है। यहाँ साझा की जाने वाली हर कहानी हमारी टीमों, साझेदारों और कृषि समुदायों की समर्पित भावना का प्रमाण है।

हमारा मिशन स्पष्ट है: किसानों और कृषि-पेशेवरों को वह कौशल, ज्ञान और तकनीक प्रदान करना जिसकी उन्हें बदलते समय में सफल होने के लिए आवश्यकता है। नवाचार और जमीनी स्तर पर जुड़ाव को मिलाकर, हम एक अधिक उत्पादक, लचीले और समावेशी कृषि क्षेत्र की नींव रख रहे हैं।

मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप इस समाचार पत्र को पढ़ें, सीखें और इसमें प्रस्तुत अवसरों में सक्रिय रूप से भाग लें। आपकी सहभागिता ही विचारों को प्रभाव में बदलती है।

डॉ. सतेंद्र सिंह आर्य
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रिय पाठकों,

CEASI का साप्ताहिक समाचार पत्र केवल गतिविधियों का सारांश नहीं है। बल्कि यह एक ऐसा मंच है, जहाँ विचारों का आदान-प्रदान, उपलब्धियों का उत्सव और भारतीय कृषि तथा इसके सहायक क्षेत्रों जैसे डेयरी, बागवानी, कृषि मशीनीकरण, जलवायु लचीलापन आदि के भविष्य के लिए हमारी साझा दृष्टि को और मजबूत किया जाता है। प्रत्येक अंक कृषि क्षेत्र और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से नवाचार, सहयोग और प्रगति की कहानियाँ लेकर आता है।

आगे बढ़ते हुए, हमारा ध्यान ज्ञान साझा करने, नवीनतम विकासों को सामने लाने, क्षमता निर्माण करने और सफलता की कहानियाँ हर स्तर पर किसान के खेत से लेकर नीति-निर्माताओं तक पहुँचाने पर रहेगा। ताकि आधुनिक उपकरण, तकनीकें और सर्वोत्तम प्रथाएँ उन तक पहुँच सकें जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

मैं स्वीकार करता हूँ कि यह समाचार पत्र अभी अपने प्रारंभिक चरण में है। मैं पाठकों और हितधारकों से आग्रह करता हूँ कि वे इसमें प्रस्तुत पहलों, प्रशिक्षणों और अद्यतनों से जुड़े रहें, और ऐसी प्रमुख उपलब्धियों व घटनाओं को साझा करें जिन्हें यहाँ प्रकाशित किया जा सके। इसके दायरे, प्रकाशन की आवृत्ति, नए अनुभाग जोड़ने और सुधार के लिए आपके विचार इसे एक आदर्श पत्रिका बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, जो हमें साथ मिलकर और अधिक मजबूत बनने के अवसर प्रदान करेगी।

जसवंत सिंह कालसी
मुख्य परिचालन अधिकारी

हमारे बारे में

हम कौन हैं:

"सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEASI)" एक स्वायत्त संस्था है, जो "एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (ASCI)" के अधीन कार्य कर रही है। यह संस्था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत किसानों, मजदूरी श्रमिकों, स्वरोजगार में लगे पेशेवरों, विस्तार कार्यकर्ताओं आदि के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण का कार्य करती है।

CEASI कृषि के विभिन्न उप-क्षेत्रों में स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों की शीर्ष संस्था है, जैसे कि:

- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेयरी स्किल्स इन इंडिया (CEDSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEHSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फार्म मेकनाइजेशन स्किल्स इन इंडिया (CEFMI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर (CoE-CRA)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर (CoE-AI)

हम क्या करते हैं:

- **कौशल विकास और क्षमता निर्माण:** कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में हितधारकों की आवश्यकताओं के आधार पर क्षमता निर्माण।
- **ज्ञान प्रबंधन:** वर्कफोर्स मानकों को समर्थन देने हेतु QPs, NOS, स्किल गैप रिपोर्ट और न्यूज़लेटर्स का विकास।
- **अनुसंधान:** उद्योग की मांगों के अनुसार आवश्यकताओं की पहचान और कौशल अंतर को पाटने के लिए अनुसंधान।
- **नीति समर्थन और परामर्श सेवाएं:** नवाचार साझा करने और क्षेत्रीय चुनौतियों को हल करने हेतु नेटवर्क का निर्माण।

हमारा विज़न

एक स्वायत्त उत्कृष्टता संस्थान जो कृषि में उच्च कौशलयुक्त कार्यबल विकसित करने के लिए समर्पित है, नवाचार, तकनीकी प्रगति और सतत प्रथाओं के माध्यम से भारतीय कृषि की समृद्धि और लचीलापन बढ़ाने के लिए कार्यरत है।

हमारा मिशन

राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उन्नत कृषि पद्धतियों में कौशल विकास के लिए अग्रणी संगठन के रूप में उभरना, जो सततता, लाभप्रदता, क्षमता निर्माण, ज्ञान प्रसार, नीति समर्थन और नवाचार आधारित अनुसंधान के माध्यम से कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करता है।

CEASI का प्रभाव:

CEASI भारतीय कृषि में एक परिवर्तनकारी बदलाव ला रहा है, जो व्यक्तियों को सशक्त बनाने, कौशल को निखारने और देशभर में समुदायों को उन्नत करने का कार्य कर रहा है।

- 15+ राज्य
- 15 एफपीओ को प्रशिक्षित और सहयोग प्रदान किया गया
- 20,000 कृषि / डेयरी पेशेवरों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया
- 5000+ उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया
- 3000+ महिलाओं को सशक्त बनाया गया
- 30,000+ जीवन को प्रभावित किया गया

कृषि मशीनरी पर जीएसटी में कटौती से किसानों को बड़ी बचत

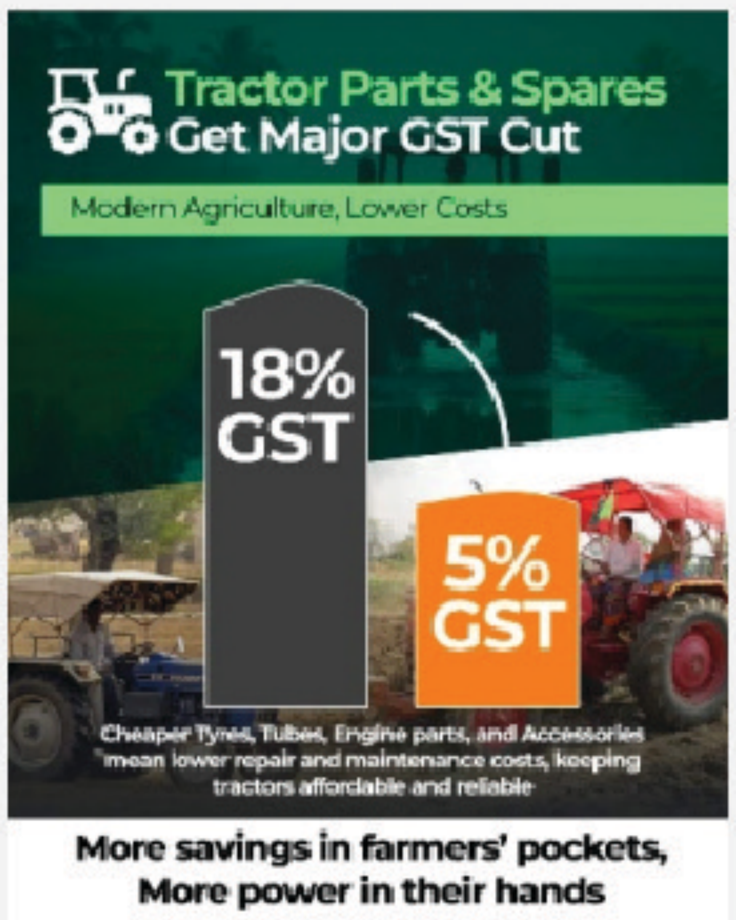

भारत के किसानों को अब कृषि मशीनरी सस्ती मिलने जा रही है। जीएसटी परिषद ने ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और सीड ड्रिल जैसी मशीनों पर कर दर 18% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है। यह बदलाव 22 सितम्बर से लागू होगा। इससे खेती की लागत घटेगी, मशीनीकरण बढ़ेगा और उत्पादन में तेजी आएगी।

नई दरों से किसानों को खरीद पर अच्छी बचत होगी। उदाहरण के लिए, 35 एचपी ट्रैक्टर लगभग 41,000 रुपये सस्ता होगा, वहीं 75 एचपी ट्रैक्टर करीब 63,000 रुपये कम दाम में मिलेगा। हार्वेस्टर पर लगभग 1.87 लाख रुपये तक की बचत होगी। छोटे औज़ार जैसे पावर टिलर, थ्रेशर और सीडर पर भी हजारों रुपये कम खर्च होंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम किसानों को आधुनिक मशीनें अपनाने में मदद करेगा। समय पर बुवाई और कटाई होने से श्रम लागत कम होगी और फसल की पैदावार व गुणवत्ता बेहतर होगी। नतीजतन किसानों की आय बढ़ने की संभावना है।

बिहार में छोटे किसानों के लिए फार्म मशीनरी बैंक का विस्तार

पटना: बिहार सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों तक आधुनिक कृषि उपकरण पहुँचाने के लिए फार्म मशीनरी बैंक (FMBs) की संख्या बढ़ाने की घोषणा की है। कृषि मंत्री व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि अब तक 569 मशीनरी बैंक खोले जा चुके हैं और चालू वित्तीय वर्ष में 38 और खोले जाएंगे।

इस योजना में 10 लाख रुपये की लागत पर बैंक स्थापित करने पर 80% तक (अधिकतम 8 लाख रुपये) सब्सिडी दी जाती है। इससे किसानों पर बोझ कम होगा और उपकरण आसानी से मिल सकेंगे। हर मशीनरी बैंक में जुताई, बुवाई/रोपाई, कटाई और गहाई के लिए कम से कम एक-एक मशीन होना अनिवार्य है।

यह सुविधा जीविका समूह, किसान क्लब, एफपीओ, एफपीसी, सहकारी समितियाँ और NABARD/ATMA से जुड़े संगठन ले सकते हैं। योजना से छोटे किसानों को बड़े किसानों जैसी तकनीकी सुविधा मिलेगी। समय पर मशीन उपलब्ध होने से कृषि कार्य आसान होगा और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी

हैदराबाद में जलवायु-लचीली तकनीकों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम

आईसीएआर-केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान (CRIDA), हैदराबाद ने 24-25 जुलाई 2022 को दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम "प्रौद्योगिकी प्रदर्शन से लचीलापन बढ़ाना" आयोजित किया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय नवाचार जलवायु लचीली कृषि (NICRA) के तकनीकी प्रदर्शन घटक के तहत हुआ।

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए आईसीएआर के उप महानिदेशक (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन) डॉ. सुरेश कुमार चौधरी ने कहा कि एनआईसीआरए ने जलवायु परिवर्तन के प्रति किसानों से लेकर नीति निर्माताओं तक जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। उनके अनुसार, कई राज्य सरकारों ने एनआईसीआरए के अनुभव से प्रेरित होकर अपनी योजनाएँ शुरू की हैं। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्रों और ग्राम संस्थाओं के योगदान की भी सराहना की।

सीआरआईडीए के निदेशक डॉ. वी.के. सिंह ने बताया कि अब मॉड्यूल आधारित दृष्टिकोण के बजाय खेती प्रणाली आधारित रणनीति अपनाई जा रही है। इसमें जोखिम और संवेदनशीलता एटलस का उपयोग कर KVK का चयन किया जा रहा है तथा राष्ट्रीय मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जैसी योजनाओं से तालमेल किया जा रहा है।

हरियाणा में 315 करोड़ की योजना से नहरों का आधुनिकीकरण

चंडीगढ़, 2 सितम्बर 2025: हरियाणा सरकार ने राज्य की सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने और आधुनिक बनाने के लिए 315 करोड़ रुपये की बड़ी योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने 54 परियोजनाओं के कार्ययोजना को स्वीकृति दी।

इस योजना के तहत 30 नहरों का पुनर्वास और 24 नहरों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। आधुनिक तकनीक से नहरों की गहराई, चौड़ाई और ढाँचा सुधारा जाएगा ताकि किसानों को समय पर पर्याप्त सिंचाई जल मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से किसानों की भूजल पर निर्भरता घटेगी और कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की समस्या भी कम होगी।

यह योजना टिकाऊ जल प्रबंधन की दिशा में एक अहम कदम है। इससे लंबे समय तक किसानों को लाभ मिलेगा और राज्य की सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी।

आंध्र प्रदेश में उर्वरक आपूर्ति और बागवानी फसलों की समीक्षा

आंध्र प्रदेश में उर्वरकों की उपलब्धता, बागवानी फसलों तथा विपणन से जुड़े मुद्दों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस मौसम में राज्य में 2,00,000 मीट्रिक टन से अधिक उर्वरक उपलब्ध कराए गए हैं। बैठक में काला बाज़ार पर रोक लगाने तथा उन किसानों के लिए सब्सिडी विकल्प तलाशने पर चर्चा हुई जो उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम कर रहे हैं। साथ ही, फसलों की बुवाई, आपूर्ति और खपत की सतत निगरानी पर विशेष बल दिया गया ताकि किसानों को समय पर सहायता मिल सके।

बैठक में यह भी रेखांकित किया गया कि बागवानी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को खेती की लागत के अनुरूप बनाया जाए, जिससे किसानों को उचित लाभ सुनिश्चित हो सके। कॉफी बागानों में नए कीट की समस्या पर भी विचार किया गया और प्रभावित फसलों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए ताकि उनका प्रसार रोका जा सके। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि ऐसे निवारक कदम उठाने वाले किसानों को उचित मुआवज़ा प्रदान किया जाएगा। बैठक ने राज्य की कृषि सुधार, फसल सुरक्षा और विपणन प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता को दोहराया।

राष्ट्रीय उद्यानिकी कार्यक्रम के तहत जलगांव केला क्लस्टर से निर्यात को नई गति

जलगांव के केला क्लस्टर को राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड के क्लस्टर विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया है, जिससे किसानों और व्यापारियों के लिए वैश्विक बाजार तक पहुँच का मार्ग प्रशस्त हुआ है। लगभग सौ करोड़ रुपये की सहायता से उत्पादन, फसलोत्तर प्रबंधन और मूल्य संवर्धन को सुदृढ़ किया जाएगा। जलगांव जिले में लगभग 68 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में केला उत्पादन होता है, विशेषकर रावेर, यावल, मुक्ताईनगर और चोपड़ा तहसीलों में। यहाँ की भूमि, जल और जलवायु के कारण उत्पादित केला देश और विदेश में अत्यधिक मांग में रहता है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले टिश्यू कल्चर पौधे, मशीनीकरण, प्रशिक्षण, गोदाम, पैक हाउस, रिपनिंग चैम्बर, प्रसंस्करण इकाइयाँ और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। साथ ही, लॉजिस्टिक्स, ब्रांडिंग और विपणन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे घरेलू और निर्यात बाजारों में प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। 15 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैले इस क्लस्टर से भंडारण की कमी से होने वाले नुकसान कम होंगे और केले की गुणवत्ता सुधरकर निर्यात में वृद्धि होगी। यह पहल जलगांव केले को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

सरकारी योजनाओं से भारत का उद्यानिकी उत्पादन 367.72 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर

नई दिल्ली: पिछले एक दशक में भारत के उद्यानिकी क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसे सरकारी योजनाओं और उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर विविधीकरण ने गति दी है। वर्ष 2024–25 के द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार कुल उद्यानिकी उत्पादन 2013–14 के 280.70 मिलियन टन से बढ़कर 367.72 मिलियन टन तक पहुँच गया है। इसमें 114.51 मिलियन टन फल, 219.67 मिलियन टन सब्जियाँ और 33.54 मिलियन टन अन्य उद्यानिकी फसलें शामिल हैं। पिछले दशक में फल उत्पादन में लगभग 30 प्रतिशत और सब्जियों में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, साथ ही उत्पादकता स्तरों में भी उल्लेखनीय सुधार दर्ज हुआ है।

यह वृद्धि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और क्लीन प्लांट प्रोग्राम जैसी पहल के कारण संभव हुई है, जिनका उद्देश्य फसलों की गुणवत्ता, उत्पादकता और किसानों की बाजार तक पहुँच को बेहतर बनाना है। इन योजनाओं के तहत उच्च गुणवत्ता वाले पौधरोपण सामग्री की आपूर्ति, तकनीक प्रदर्शन और प्रशिक्षण हेतु उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना तथा फसलोत्तर अवसंरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है। इन प्रयासों से भारत का उद्यानिकी क्षेत्र घरेलू और वैश्विक बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बन रहा है।

बागलकोट में बेल फल की खेती और विपणन पर कार्यशाला

बागलकोट: बागलकोट स्थित उद्यानिकी विज्ञान विश्वविद्यालय में बेल फल (जूस बिल्व) की खेती, विपणन और उपयोग पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। विशेषज्ञों ने एगले मार्मेलोस के नाम से ज्ञात इस फसल की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह विशेष रूप से कल्याण कर्नाटक जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब इस फसल को कर्नाटक में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे बागवानी में विविधीकरण के नए अवसर मिलेंगे।

इस पहल के तहत राज्य की चार कृषि विश्वविद्यालयों ने गोधरा स्थित शुष्क उद्यानिकी केंद्रीय संस्थान और उत्तर प्रदेश की नर्सरियों से 7,000 से अधिक ग्राफ्टेड पौधे प्राप्त किए हैं। इन पौधों को प्रायोगिक नर्सरियों और चुनिंदा किसानों में वितरित किया जाएगा ताकि परीक्षण खेती की जा सके। कार्यशाला में पंजीकृत प्रतिभागियों को भी पौधे प्रदान किए गए। इस आयोजन ने बेल फल की क्षमता को रेखांकित किया, जो किसानों के लिए नए अवसर प्रदान करने के साथ-साथ जल-अभाव वाले क्षेत्रों में सतत बागवानी को प्रोत्साहित करेगा।

राजस्थान ने रखा लक्ष्य: देश का सबसे बड़ा डेयरी हब बनने की दिशा में कदम

राजस्थान ने स्वयं को देश का सबसे बड़ा डेयरी हब बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिसमें किसानों, पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। जयपुर में आयोजित गौ महाकुंभ में राज्य के डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने और पशुधन प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए प्रमुख पहलों को रेखांकित किया गया।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत ₹500 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें से ₹468 करोड़ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। उत्पादकों को समर्थन देने के लिए प्रति लीटर ₹5 की सब्सिडी दी जा रही है और प्रति किलोग्राम वसा का औसत मूल्य ₹864 सुनिश्चित किया गया है।

अन्य उपायों में गोपाल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण सुविधाओं का विस्तार, 33,000 से अधिक दुग्ध उत्पादकों को ₹3 लाख का बीमा कवर, तथा गौ संरक्षण और संवर्धन योजनाओं के तहत ₹2,791 करोड़ का आवंटन शामिल है। पंजीकृत गौशालाओं को प्रति गाय प्रतिदिन ₹50 और बछड़ों के लिए ₹25 की सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, पंचायत स्तर पर अवसंरचना विकास के लिए नंदीशाला सहयोगिता योजना के तहत ₹62 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

डेयरी उत्पादों पर जीएसटी में कटौती से बढ़ेगी सुलभता और खपत

डेयरी उत्पादों पर जीएसटी में कटौती से बढ़ेगी सुलभता और खपत

डेयरी उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) को 12% से घटाकर 5% करने के हालिया निर्णय का देश की प्रमुख डेयरी सहकारी समितियों ने स्वागत किया है। उनका मानना है कि यह कदम दूध आधारित उत्पादों को अधिक सुलभ बनाएगा, खपत को बढ़ावा देगा और लाखों किसानों को सहारा देगा।

अमूल के प्रबंध निदेशक श्री जयेन मेहता ने कहा कि इस निर्णय से गुजरात के 36 लाख किसान परिवारों सहित देशभर के 10 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ होगा जो डेयरी उद्योग से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि अमूल के अंतर्गत आने वाले 30 से अधिक डेयरी और खाद्य उत्पादों पर अब कम कर दरें लागू होंगी, जिससे खपत में वृद्धि होगी और दुग्ध उत्पादकों की आय में सतत वृद्धि सुनिश्चित होगी।

मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक श्री मनीष बैंडलिश ने भी इस सुधार को सराहा और इसे डेयरी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पनीर, चीज़, घी, मक्खन, यूएचटी दूध, पेय पदार्थ और आइसक्रीम पर कम जीएसटी से उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद अधिक किफायती होंगे, पैक्ड वैल्यू-एडेड डेयरी उत्पादों की मांग मजबूत होगी और किसानों के लिए बेहतर अवसर पैदा होंगे, साथ ही उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बेहतर मूल्य पर मिलेंगे।

हासन की ₹790 करोड़ की मेगा डेयरी मार्च 2026 तक होगी शुरू, पर्यटन और युवाओं के लिए नए अवसर

₹790 करोड़ से अधिक की लागत से बन रही मेगा डेयरी परियोजना का उद्घाटन मार्च 2026 तक हासन में होने जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र के डेयरी क्षेत्र को मजबूत करना है, साथ ही पर्यटन और युवाओं की भागीदारी के नए अवसर खोलना भी है। यह सुविधा शहर के बाहरी इलाके में केआईएडीबी औद्योगिक क्षेत्र में हासन कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स सोसाइटी यूनियन के तहत बनाई जा रही है।

आगामी प्लांट से हासन डेयरी की प्रसंस्करण और क्षमता निर्माण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जो पहले से ही कर्नाटक की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली डेयरियों में गिनी जाती है। हाल के वर्षों में 240 रिक्त पद और भर्ती न होने के बावजूद, यूनियन ने केवल 1.69% आय प्रशासनिक खर्चों पर खर्च कर कुशलतापूर्वक संचालन किया है, जबकि अन्य संघों में यह कहीं अधिक है।

डेयरी का टर्नओवर भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, जो 1990 के दशक के मध्य में मात्र ₹4 करोड़ था, आज बढ़कर ₹3,000 करोड़ हो गया है। मेगा सुविधा शुरू होने के साथ, यूनियन डेयरी पर्यटन और युवाओं पर केंद्रित पहलों सहित अपनी गतिविधियों में और विविधता लाने की योजना बना रही है।

मध्यप्रदेश में एआई तकनीक से प्रजनन, कमधेनु योजना के तहत मिलेगी ₹14 लाख तक की सब्सिडी

मध्यप्रदेश, उत्तराखंड के बाद दूसरा राज्य बन गया है जिसने मादा बछड़ों के उत्पादन के लिए सेक्स-सॉर्टेड सीमेन तकनीक पर आधारित कृत्रिम गर्भाधान (AI) को अपनाया है। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में Y गुणसूत्रों को फ़िल्टर कर दिया जाता है, जिससे मादा जन्म की संभावना 90% से अधिक हो जाती है। इससे दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा और आवारा पशुओं की समस्या में कमी आएगी।

भोपाल स्थित केंद्रीय सीमेन स्टेशन फिलहाल हर साल दो लाख डोज़ तैयार करता है, जिसे अगले पाँच वर्षों में बढ़ाकर 25 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है। एक डोज़ की लागत लगभग ₹850 है, लेकिन किसानों को यह सरकार की सब्सिडी के बाद मात्र ₹100 में उपलब्ध कराया जा रहा है।

साथ ही, डॉ. बी.आर. अंबेडकर कमधेनु योजना के तहत बड़े स्तर पर डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। 25 दुग्ध पशुओं की प्रत्येक यूनिट पर लगभग ₹42 लाख की लागत आती है, जिसमें एससी/एसटी किसानों को ₹14 लाख और ओबीसी/सामान्य वर्ग के किसानों को ₹10 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। किसान अधिकतम आठ यूनिट तक स्थापित कर सकते हैं, जिसमें अनिवार्य प्रशिक्षण और तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि होगी।

यह योजना दुग्ध उत्पादन को 10 लाख लीटर से बढ़ाकर 50 लाख लीटर प्रतिदिन तक ले जाने, रोजगार सृजन, उत्पादकता बढ़ाने और अन्य राज्यों पर निर्भरता घटाने का लक्ष्य रखती है।

भारत में कृषि परिवर्तन को गति दे रही है तकनीक: बीज से बाज़ार तक

भारतीय कृषि एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, जहाँ आधुनिक तकनीकें "बीज से बाज़ार तक"की यात्रा को नया रूप दे रही हैं। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस , इंटरनेट ऑफ थिंग्स , ड्रोन, सैटेलाइट मैपिंग और जैम ट्रिनिटी जैसी पहलें खेती की पद्धतियों में क्रांति ला रही हैं और किसानों की आजीविका को बेहतर बना रही हैं।

AI आधारित समाधान जैसे किसान ई-मित्र, एक बहुभाषी चैटबॉट, रोज़ लाखों किसानों की पूछताछ संभाल रहा है। वहीं, राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली एआई और एमएल के जरिए 61 फसलों और 400 कीटों की निगरानी कर शुरुआती स्तर पर ही रोगों का पता लगा रही है।

सैटेलाइट आधारित कार्यक्रम जैसे FASAL और Krishi-DSS फसल पूर्वानुमान, क्षेत्रफल के आँकड़े और भू-स्थानिक निर्णय सहयोग उपलब्ध करा रहे हैं।

ड्रोन अब छिड़काव, निगरानी और प्रिसिजन फार्मिंग में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता योजनाएँ लागू की गई हैं। केवल नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ही 15,000 ड्रोन महिला स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने का लक्ष्य है।

वहीं, जैम ट्रिनिटी किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित कर रही है।

इन सभी पहलों के साथ, भविष्य की तस्वीर साफ़ है—भारत में कृषि का विकास तकनीक आधारित होगा, जो उत्पादकता, स्थिरता और लचीलापन सुनिश्चित करेगा।

नकली कृषि उत्पाद रोकने के लिए हेल्पलाइन शुरु

नई दिल्ली, 3 सितम्बर 2025: किसानों को नकली बीज, खाद और कीटनाशकों से बचाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने नई हेल्पलाइन शुरू की है। किसान अब टोल-फ्री नंबर 1800-180-1551 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं और तुरंत सहायता पा सकते हैं।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की शिकायतों का समय पर निवारण उतना ही जरूरी है जितना नई योजनाएँ बनाना। उन्होंने बताया कि सभी शिकायतों की निगरानी की जाएगी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा होगी।

हाल ही में मध्यप्रदेश सहित कई जगह नकली कृषि रसायनों से फसल नुकसान हुआ, जिसके बाद दोषी कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और लाइसेंस निलंबित किए गए। अब सरकार ने आकस्मिक निरीक्षण और कड़े नियम लागू करने की भी तैयारी की है।

यह पहल किसानों को सुरक्षित रखने, फसल हानि घटाने और असली कृषि उत्पाद खेतों तक पहुँचाने में मदद करेगी

CEDSI ने असम में गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा पर पहला जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किय

स्किल्स इन इंडिया (CEDSI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने अपना पहला गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम 8 सितम्बर 2025 को डेयरी डेवलपमेंट निदेशालय, खानापारा, असम में सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस कार्यक्रम में असम के विभिन्न हिस्सों से आए 30 प्रतिभागियों, जिनमें पारंपरिक मिठाई बनाने वाले, डेयरी कोऑपरेटिव सोसायटी (DCS) के सदस्य और स्ट्रीट फूड विक्रेता शामिल थे, ने हिस्सा लिया।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (GMP), व्यक्तिगत स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा की मूल बातें, सामग्री का सुरक्षित भंडारण और उपयोग, स्ट्रीट वेंडिंग मानक, कचरा प्रबंधन और कीट नियंत्रण जैसे विषयों पर व्यावहारिक जानकारी प्राप्त की। साथ ही, उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप काम करने के लिए आवश्यक अनुपालन संबंधी मार्गदर्शन भी दिया गया।

कार्यक्रम के अंत में प्रत्येक प्रतिभागी को CEDSI का प्रमाण पत्र दिया गया, जो सुरक्षित, स्वच्छ और बेहतर गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह पहल CEASI, ASCI और स्किल इंडिया के सहयोग से आयोजित की गई, जो स्वस्थ समुदाय बनाने, उपभोक्ता विश्वास बढ़ाने और असम में मिठाई, डेयरी और स्ट्रीट फूड क्षेत्रों की स्थिरता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

'सश्वत मिठास' पहल के तहत अयोध्या में जलवायु-स्मार्ट गन्ना खेती को सशक्त बनाना

सश्वत मिठास पहल के तहत, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEASI) ने UPL SAS लिमिटेड के सहयोग से अयोध्या में टिकाऊ गन्ना खेती की प्रथाओं को बढ़ावा देने का कार्य शुरू किया है। अब तक, 500 किसानों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिसमें 90 असंगठित और 3 संगठित किसान समूह शामिल हैं, ताकि उनकी मौजूदा खेती पद्धतियों का आकलन किया जा सके और सुधार की संभावनाएँ पहचानी जा सकें। इन निष्कर्षों के आधार पर गाँव-स्तर पर प्रदर्शन प्लॉट स्थापित किए गए हैं, जहाँ पानी के कुशल उपयोग, मिट्टी की सेहत प्रबंधन और जैविक इनपुट के प्रयोग जैसी बेहतरीन प्रथाएँ प्रदर्शित की जा रही हैं।

किसानों की भागीदारी और सीखने की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए अब तक 97 रिटेलर विज़िट, 9 फील्ड डे, 4 संगठित बैठकें और 94 असंगठित बैठकें आयोजित की गई हैं। इन मंचों ने किसानों को विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करने, जमीनी चुनौतियों पर चर्चा करने और जलवायु-संवेदनशील खेती की प्रथाओं के व्यावहारिक उपयोग को देखने का अवसर दिया है।

मैदानी शोध, जीवंत प्रदर्शन और हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से यह पहल किसानों को ऐसी पर्यावरण-अनुकूल और संसाधन-कुशल तकनीकें सिखा रही है, जो उनकी पैदावार बढ़ाती हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करती हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रति उनकी सहनशीलता को मजबूत करती हैं। इस पहल का बड़ा लक्ष्य केवल गन्ने की उत्पादकता बढ़ाना ही नहीं, बल्कि अयोध्या क्षेत्र में पर्यावरणीय स्थिरता और समावेशी कृषि विकास का एक मॉडल तैयार करना भी है।

CEFMI ने हरियाणा में FPO नेतृत्व को सशक्त बनाने के लिए EKL CSR फाउंडेशन के साथ साझेदारी की

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फार्म मैकेनाइजेशन स्किल्स इन इंडिया (CEFMI) ने एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड के सहयोग से 25 से 27 अगस्त 2025 तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित एस्कॉर्ट्स कुबोटा एडवांस्ड फार्मिंग इंस्टिट्यूट (EKFAI) में 3 दिवसीय आवासीय क्षमता-विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 29 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का प्रतिनिधित्व करने वाले 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण का उद्देश्य FPOs की संगठनात्मक शासन व्यवस्था और संरचना को मजबूत करना, प्रतिभागियों की खेती के मशीनीकरण से जुड़ी समझ को बढ़ाना और एग्री-बिजनेस गतिविधियों के लिए वित्तीय तंत्र के बारे में उनकी जानकारी को सुदृढ़ करना था। विशेष जोर नेतृत्व कौशल विकसित करने, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने और ऐसे टिकाऊ मशीनीकरण समाधानों को प्रोत्साहित करने पर दिया गया जो सीधे सदस्य किसानों को लाभ पहुंचा सकें।

इंटरैक्टिव सत्रों, केस स्टडीज़ और समूह चर्चाओं के माध्यम से इस कार्यक्रम ने FPO नेताओं को अपने अनुभव साझा करने, संचालन से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करने और सामूहिक विकास के अवसरों की खोज करने का मंच प्रदान किया। आवासीय प्रारूप ने प्रतिभागियों को एक गहन शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराया, जिससे सहकर्मी-से-सहकर्मी सीखने और सहयोग को बढ़ावा मिला।

CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR
AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

(CEASI), Unit No. 101, First Floor, Greenwoods Plaza, Block 'B' Greenwoods City, Sector-45, Gurugram, Haryana-122009

+91 74287 06078

info@cedsi.in

www.ceasi.in

@ceasi_india